भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4670

दिनांक 21 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

राष्ट्रीय फीडर निगरानी प्रणाली के उद्देश्य

4670. श्री भरतसिहंजी शंकरजी डाभीः

श्रीमती स्मिता उदय वाघः

श्री प्रदीप कुमार सिंहः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय फीडर निगरानी प्रणाली (एनएफएमएस) के प्रमुख उद्देश्य, विशेषताएँ और तकनीकी रूपरेखा क्या हैं और यह संपूर्ण देश में ग्रामीण और शहरी फीडरों की वास्तविक समय डेटा निगरानी में किस प्रकार सहायक है;

(ख) वर्तमान में एनएफएमएस प्लेटफार्म के साथ निगरानी और एकीकृत किए जा रहे फीडरों की कुल संख्या कितनी है और साथ ही इसमें शामिल वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की संख्या विशेषकर महाराष्ट्र में कार्यरत कंपनियों की संख्या कितनी है;

(ग) महाराष्ट्र के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में एनएफएमएस का कितना कार्यान्वयन किया गया है;

(घ) क्या जलगाँव जैसे जिले इस प्रणाली के अंतर्गत शामिल किए गए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) देश में फीडर-स्तरीय पारदर्शिता में सुधार, समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों को कम करने, और कृषि उपभोक्ताओं तथा ग्रामीण परिवारों को विश्वसनीयता पारदर्शिता, दक्षता और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने में एनएफएमएस का क्या प्रभाव है; और

(च) क्या सरकार ने एनएफएमएस डेटा के संबंध में, इस आधार पर राज्य उपयोगिताओं के लिए कोई कार्यनिष्पादन-संबंधी दिशानिर्देश या मूल्यांकन मानदंड जारी किए हैं और साथ ही उक्त राज्य में कर्मियों को प्रशिक्षित करने और अवसंरचना के आधुनिकीकरण के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (च) : राष्ट्रीय फीडर निगरानी प्रणाली (एनएफएमएस) का उद्देश्य निर्बाध मशीन-टू-मशीन (एम2एम) स्वचालित आंकड़ों के प्रवाह के आधार पर आपूर्ति घंटों और आउटेज सहित मापदंडों के लिए 11 केवी फीडरों की निगरानी करना है।

मूलतः, एनएफएमएस एक निगरानी डैशबोर्ड है जो संचार योग्य फीडर मीटरों से आंकड़े एकत्र करता है। यह वितरण कंपनियों को विद्युत वितरण प्रणालियों के कार्य निष्पादन पर नज़र रखने और सुधार के क्षेत्रों को चिह्नित करने में सक्षम बनाएगा। एनएफएमएस डैशबोर्ड का एटीएंडसी हानियों या विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता और दक्षता में

सुधार पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन यह कंपनियों और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवश्यक कदम उठाने में सक्षम बनाने हेतु विद्युत आपूर्ति मापदंडों की निगरानी करने में सहायता करता है।

निगरानी को सुगम बनाने और अवसंरचना के आधुनिकीकरण के लिए, संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) के अंतर्गत स्मार्ट फीडर मीटरिंग कार्यों को संस्वीकृति दी गई है। यूटिलिटि फीडर और वितरण ट्रांसफार्मर पर संस्थापित मीटरों सहित, स्थापित मीटरों से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग कर सकती हैं, जिससे ऊर्जा लेखा परीक्षा करने और उच्च हानि वाले क्षेत्रों को चिह्नित करने में मदद मिलेगी। इन जानकारियों का उपयोग तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों को कम करने के लिए प्रभावी ढंग से किया जा सकता है।

अब तक 72 वितरण यूटिलिटि के कुल 2,49,507, 11 केवी फीडरों में से 2,06,767 फीडरों को एनएफएमएस के साथ एकीकृत किया जा चुका है। जलगाँव जिले सहित महाराष्ट्र राज्य के 5 वितरण यूटिलिटि के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के 26,461, 11 केवी फीडरों में से 26,272 फीडरों को एनएफएमएस के साथ एकीकृत किया जा चुका है।

आरडीएसएस के अंतर्गत, अवसंरचना कार्यों के लिए धनराशि जारी किए जाने को, 90% से अधिक फीडर मीटरों (विशेष श्रेणी के राज्यों के मामले में 85%) का राष्ट्रीय फीडर निगरानी प्रणाली से संचार से जुड़ा होने के साथ लिंक किया गया है। इसके अलावा, आरडीएसएस के अंतर्गत स्मार्ट मीटरिंग संबंधी कार्यों के लिए वितरण यूटिलिटी के कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब तक, यूटिलिटी कर्मचारियों के 1,682 कनिष्ठ कर्मचारियों (लाइनमैन, तकनीशियन और गैर-तकनीकी कर्मचारी) को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

****